कुतुब मीनार के अंतर्गत आने वाली भूमि पर अवैध कब्जा

6637 **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :**
श्री अनन्तराम जायसवाल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐतिहासिक स्मारक कुतुब मीनार के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सरकारी भूमि के बहुत बड़े हिस्से पर भू-माफिया ने कब्जा कर लिया है और भू-राजस्व के अभिलेखों के कालम संख्या 6 में भी इसे अवैध कब्जा दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपर्युक्त भूमि को उक्त भू-माफिया से खाली कराने का विचार रखती है; यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार इस संबंध में क्या निर्णय लेना चाहेगी और कब तक ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुतुब परिसर की संरक्षित सीमाओं के बाहर, राज्य सरकार की भूमि के एक हिस्से पर अवैध कब्जा किया गया है, किंतु भू-राजस्व के अभिलेखों (खसरा गिरदावरी) के कालम संख्या 6 में इस भूमि को अवैध कब्जे के अधीन नहीं दिखाया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सरकारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटाए जाने के लिए इस मामले को दिल्ली पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ उठाया है। दिल्ली पुलिस ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर अवैध कब्जे के एक हिस्से को पहले ही हटा दिया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अब शेष अवैध कब्जे को शीघ्र ही हटाए जाने के लिए इस मामले को दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

उच्च शिक्षा के निजीकरण का प्रभाव

6638 **श्री अनन्तराम जायसवाल :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संस्थाओं को फायदा पहुंचाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर देश में उच्च शिक्षा के निजीकरण संबंधी प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दबाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं और शिक्षा के निजीकरण का शिक्षण संस्थाओं के अस्तित्व, शिक्षा के स्तर, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और छात्रों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो शिक्षा के विचाराधीन निजीकरण के क्या कारण हैं तथा दिनांक 31 मार्च, 1995 के दैनिक हिन्दुस्तान में पृष्ठ संख्या 7 पर "उच्च शिक्षा का निजीकरण" शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निजीकरण, राज्य से निजी उद्यमों को पूर्ण या आंशिक रूप से नियंत्रण के हस्तांतरण की ओर संकेत करता है। उच्च शिक्षा के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।